



अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा-2014

आपका आह्वान करती है कि

अपने हकों को हासिल करने के लिए एकजुट संघर्ष करो!

आज़ादी के लगभग सात दशक बाद भी,

- देश के करोड़ों बच्चों और युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा का सपना उनकी पहुंच से कोसों दूर है।
- हमें अपनी हाड़-तोड़ मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा जबरन शिक्षा खरीदने के लिए देना पड़ रहा है, जबकि इस संवैधानिक अधिकार के लिए हम अनिवार्य रूप से टैक्स व अतिरिक्त शिक्षा उपकर (सेस) भी भरते हैं।
- देश के बहुसंख्यक वंचित वर्गों – जिसमें दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, विकलांग और हाशिए पर धकेले गए अन्य तबके शामिल हैं – और खासकर इन तबकों की महिलाओं को, पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक से लेकर उच्च और पेशेवर शिक्षा के हरेक स्तर पर शिक्षा से वंचित रखा गया है।
- हम पर एक भेदभावपूर्ण और बहुपरती शिक्षा व्यवस्था थोपी गई है, जिसमें अमीर लोग तो मोटी रकम देकर महंगे निजी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में अपने लिए जगह खरीद लेते हैं, लेकिन गरीबों को जबरन घटिया स्तर के निजी व सरकारी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में ठेल दिया जाता है।
- शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षकों के नियमित कैंडर को बड़े पैमाने पर ठेकाकरण और बेतुके अध्यापक शिक्षण के जरिए पूरे देश में बरबाद किया गया है।
- कालेजों व विश्वविद्यालयों के कैंपस में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, प्रतीकों, आवाज़ों व तरीकों पर दिन-ब-दिन हमले बढ़ते जा रहे हैं ताकि देश के युवाओं का जनपक्षीय राजनीतिकरण रोका जा सके।
- शिक्षा के अर्थ को इस हद तक विकृत किया गया है कि यह देश की समाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम और समतामूलक व न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक व मानवीय नागरिकों का निर्माण करने की बजाय वैश्विक बाजार के लिए गुलाम मानसिकता के कुशल कामगार ही बनाए।
- शिक्षा के जरिए धर्म-निरपेक्षता, आलोचनात्मक चेतना व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की जगह इसमें सांप्रदायिक ताकतों को नफ़रत, भेदभाव व विभाजन का जहर घोलने की छूट दी जा रही है ताकि ये जन-विरोधी सांप्रदायिक ताकतें नवउदारवाद के हमले के खिलाफ हमारे एकजुट संघर्ष को तोड़ने का काम करें, ठीक उसी तरह जैसा इन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के वक्त भी किया था।

क्या आप भारत और उसके लोगों के खिलाफ जारी इस क्रूर षड़यंत्र की ओर चुप्पी साधे ताकते रहेंगे?

हम, भारत के लोग, अपने गणतंत्र के पैसठवें साल में यह संकल्प लेते हैं कि हमसे शिक्षा का अधिकार छीनने वाली कारपोरेट पूंजी की ताकतों और उच्च वर्गों, ऊंची जातियों व पितृसत्तात्मक ढांचे के शोषण के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे।

हम यह ऐलान करते हैं कि

कक्षा 12वीं तक समान पड़ोसी स्कूल व्यवस्था समेत,

‘केजी से पीजी तक’

सरकार द्वारा वित्त-पोषित और पूरी तरह मुफ्त समान शिक्षा व्यवस्था

के लिए लंबी लड़ाई जारी रखेंगे

जिसमें बहुभाषीयता के संदर्भ में हम सबकी मातृभाषाएं शिक्षा का माध्यम हों और साथ ही भारत की भाषाओं को व्यापार और लेन-देन, और विज्ञान व तकनीकी समेत राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में स्थापित किया जाए क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है देश के हरेक नागरिक के लिए हर स्तर पर लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक, समतामूलक व मानवीय शिक्षा मुकम्मल कराने का।

शिक्षा पर कॉर्पोरेट पूंजी और उसके सांप्रदायिक दलालों के दोहरे हमले के खिलाफ एकजुट हो!

जाति और पितृसत्ता के ढांचे को ध्वस्त करने के लिए संगठित हो!

शिक्षा और मुक्ति के जनसंघर्षों को आगे बढ़ाओ!!

गुलाम बनाने वाली शिक्षा का प्रतिरोध करो!

मुक्तिकामी शिक्षा के लिए संघर्ष करो!!



अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंच

और इसके 45 सदस्य-संगठनों व 200 से भी ज्यादा बिरादराना संगठनों
द्वारा आयोजित

अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा-2014

2 नवंबर 2014 को लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण व मानवीय भारत के निर्माण के लिए इरोम शर्मिला के संघर्ष को सलाम करते हुए शिक्षा संघर्ष यात्रा देश के विभिन्न राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में जिला स्तर की यात्राओं व भारत के उत्तरपूर्व, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम व पूर्व से आंचलिक यात्राओं के साथ शुरू होगी।

4 दिसंबर 2014 को लोगों के जीवन व हकों पर क्रूर साम्राज्यवादी हमले के खिलाफ भोपाल गैस कांड के शिकार लाखों लोगों के 30 साल से चल रहे लंबे संघर्ष से एकजुटता जाहिर करते हुए यात्रा का भोपाल में समापन होगा।

अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा का मानना है कि शिक्षा वैश्विक बाजार की लूट के लिए गुलाम कामगार बनाने का ज़रिया कतई नहीं है, बल्कि यह,

- जनता की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने;
- साम्प्रदायिक, जातिवादी, पितृसत्तात्मक, संकीर्ण व विकलांगता-विरोधी पूर्वाग्रहों एवं भेदभाव, अतार्किकता और अंधविश्वास की बेड़ियों को तोड़ने; और
- समानता, सामाजिक न्याय व विविधता और सामाजिक बदलाव के लिए ज़रूरी आलोचनात्मक वैज्ञानिक चेतना का विकास करते हुए देश में

लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रबुद्ध समाज
के निर्माण का सशक्त माध्यम है।

संविधान में निहित समतामूलक व भेदभाव से मुक्त शिक्षा

को हासिल करने की पूर्व शर्त है कि उन नवउदारवादी नीतियों को ध्वस्त किया जाए जो

- शिक्षा में मुनाफ़ाखोरी को बढ़ावा दे रही हैं;
- सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) व विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ़डीआई) के ज़रिए जनता की संपत्ति और सार्वजनिक धन को निजी हाथों में सौंप रही हैं;
- शिक्षा को विश्व व्यापार संगठन-गैट्स की देश की संप्रभुता छीननेवाली शर्तों पर बिकाऊ माल बना रही हैं; और
- जनमानस में सांप्रदायिक, मशीनीकृत व गुलाम सोच को पोषित करते हुए वैश्विक बाजार के हित में शिक्षा के उद्देश्य को ही विकृत कर रही हैं।

शिक्षा के इस संविधान-सम्मत लक्ष्य को हासिल करने के लिए शिक्षा से निजीकरण, बाज़ारीकरण और सांप्रदायीकरण के नवउदारवादी एजेंडे को पलटवाने के लिए एकजुट संघर्ष तेज करो!

शिक्षित हों! संघर्ष करो! संगठित हों!
और अपनी भाषाओं की मुक्ति, ज्ञान पर अपना हक वापस हासिल करने और शिक्षा के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई जारी रखो!

सबको शिक्षा एक समान, लेकर रहेगा हिंदोस्तान!

‘अखिल भारत शिक्षा संघर्ष यात्रा’ संयोजक:

प्रिंस गजेंद्र बाबू (चेन्नई) - 09445683660; गुड्डी एस.एल. (मुंबई) - 09869059860; लोकेश मालती प्रकाश (भोपाल) - 09407549240;
अभाशिअम संगठन सचिव: रमेश पटनायक (हैदराबाद) - 09440980396; अभाशिअम कार्यालय सचिव: विक्रम अमरावत (अहमदाबाद) - 08128293711
ईमेल - aifрте.secretariat@gmail.com; aifрте.shikshayatra2014@gmail.com; वेबसाइट - www.aifрте.in